

सं. 14036/3772013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 27/5/2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त,
लोक सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमान/श्रीमती कन्टिया लाल सेठ द्वारा
मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 18.4.2013 के उपर्युक्त आर टी
आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 05.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि
आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपयुक्त कार्रवाई करने तथा उपरोक्त आवेदक को सीधे सूचना प्रदान
करने हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय/-----में जमा कर दिया गया है।

भवदीया,

एस. सुधा
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष : 23092856

Issued with end
1404/1409
27/5.

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

श्री/श्रीमनि/श्रीमती कन्टिया लाल सेठ पुत्र स्व. श्री मंगल सेठ सेठ
वा.नं. 5बी/4, तिहाड़ जेल नं. 3, नई दिल्ली-110064

इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त
सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

935

सेवा में,

माननीय मुख्य सचिव सा. (गृह)

(भारत सरकार)

नैथिंगलान कार्यालय, नई दिल्ली,

विषय: - सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना।

माननीय श्री मान जी,

प्रार्थी द्वारा प्रांगी गड़ि सूचना का सम्बन्ध प्रार्थी के जीवन व स्वतन्त्रता से है, कृपया प्रार्थी को, प्रार्थी द्वारा प्रांगी गड़ि सूचना 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

श्रीमान जी, प्रार्थी को भारत सरकार की दिल्ली पुलिस ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं पर करत हुए, गैर संवैधानिक तरीके से केस अगानर, दिल्ली तिहाड़ जेल में करीब साइ आठ साल से बन्द कराया हुआ है।

दिल्ली की भ्रष्ट पुलिस ने, प्रार्थी को, सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005, के तहत सूचना प्रांगने पर (जिससे पुलिस द्वारा बनाये गये ग्रेट रेप केस का खुलासा होने के डर से) गूढा केस अगानर जांसाया गया है।

प्रार्थी पर जो केस अगया गया है वह केस P.S.: NDLS का है जिसका F.I.R. No. 147/04, dt. 19/04/2004 है और यह केस द्वारा: 302, 201.1.1.C का है, इस केस में पुलिस अधिकारियों द्वारा द्वारा :- 173 के अन्तर्गत, अन्तिम रिपोर्ट, जाबता मौलवारी, श्री दिनांक 01/06/2005 को तुरकील कर चुके थे, जिसमें बनाये गये मुजरिओं के रंगीन इस्तेदार/पोस्टर श्री जरी किये गये थे और मुजरिओं के बाबत सूचना देने वाले को 10,000/- के इनाम देने की घोषणा की गड़ि थी।

भ्रष्ट दिल्ली पुलिस ने इस कार्यवाही पर पर्ये डालकर, दुबारा एक नई कहानी अगानर उपरोक्त केस प्रार्थी पर धोप दिये, और अदालत में दायल चालू हो गया, प्रार्थी ने इस बाबत चालाग मिलने के बाद, अदालत को इस बाबत लप्रमाणों की और पुलिस द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से पर्ये उठाने की बहुत कोशीश की, और उपरोक्त केस में गमोड़े मुजरिओं के इस्तेदार, और पुलिस द्वारा जमा की गड़ि अन्तिम रिपोर्ट, अदालत में अगानर, उसकी एक-एक कोपी देने की प्रांग की, लेकिन भ्रष्ट पुलिस ने और अदालत ने नही सुनी, (कोपीयां नही दी)।

प्रार्थी ने इस्तेदार और अन्तिम रिपोर्ट की कोपीयां लेने हेतु माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 14/09/2006 को अपील दापर की जिसपर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रार्थी की अपील नं. 21C/SS/A/2006/000906 और 000679 पर दिनांक 03/02/2012 को

Recd on
26.04.2013

आइर पास करके, प्रार्थी को उपरोक्त केस में बनाये गये प्रगोड़े मुजरीमों के इस्तेदार और पुलिस द्वारा दारवील की गई अनिप्रतिषेधि की कोपीयां पुलिस महकमों से मिलवाई, जिसकी लोटे कोपीयां 12 पेज साथ संलग्न हैं. और मुजरीमों के इस्तेदार अदालत की आइल में प्रोद्व है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथना है कि जिसका प्रावधान न हो वह दंड नहीं दिया जा सकता।

अतः प्रार्थी माननीय मुख्य सचिव (गृह) भारत सरकार मोथे बलमक कार्यालय, नई दिल्ली, से प्रार्थना करता है कि कृपया प्रार्थी को सूचना दें :-

✓ No.1 - - - - जिस किसी भी केस में Final Report, Under Section 173, Criminal Procedure Code, (एक साल से ज्यादा समय तक टालीश करने के बाद) दारवील की गई हो, और जिसमें मुजरीमों के इस्तेदार भी जारी किए गये हो, ऐसा केस एक नई कदानी बनाकर, किसी अन्य व्यक्ति/महिला पर, लगाया जा सकता है ?
कृपया इस बाबत जानकारी/सूचना दें।

✓ No.2 - - - - किसी व्यक्ति/महिला के रंगीन इस्तेदार जारी करने पुलिस द्वारा उसे प्रगोड़ा घोषित करने, उसके पकड़वाने पर इनाम की घोषणा के बाद भी पकड़ में ना आने पर कई साल के बाद, उसी केस में किसी अन्य व्यक्ति/महिला को प्रगोड़े मुजरीमों की जगह मुजरीम बनाया जा सकता है ?
पुलिस द्वारा प्रगोड़ा घोषित किया गया अपराधी जिसके इस्तेदार भी जारी किए गये हो, उसकी जगह, नई कदानी बनाकर वह केस किसी अन्य दूसरे व्यक्ति/महिला पर बनाकर उन्हे जेल में डलवाया जा सकता है ; क्या ऐसा कोई कानून में प्रावधान है।
कृपया इस बाबत पूर्ण जानकारी/सूचना दें।

✓ No.3 - - - - किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित किया जा सकता है, ?
प्रार्थी क्या प्रगोड़े मुजरीमों के संदर्भ में कानूनी प्रावधान है तो कृपया प्रार्थी को उस प्रावधान की कोपी सहित सूचना दें।
अन्यथा प्रार्थी को गैर कानूनी तरीके से बन्दी बनाकर न्यायिक दिसासत में रखने का कारण बताएँ।

कृपया प्रार्थी को प्रांगी गई सूचना 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रार्थी संदेव - आगारी रहेगा।

अन्ववाद सहित
दिनांक 18/04/2013,
समय दुपहर 01.00 बजे
स्थान दिल्ली सिविल
द्वारा रजि. पोस्ट,
I.P.O. No. 03F 420660.

प्रार्थी
कन्हैया लाल सेठ पुत्र शक्ति श्री मंगल सेन सेठ
पता: वडि नं. 5 B/4,
तिहाड जेल नं. 3,
नई दिल्ली - 110064